

ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी

लखनऊ। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 18 प्रस्ताव पास हुए। इसमें दो नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने को मंजूरी, संभल रिपोर्ट, ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला शामिल है। इसका फायदा उन छात्राओं को होगा, जिनके परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये तक होगी।

दिव्यांग छात्राओं, शहीदों और निराश्रित परिवार की बेटियों पर आय सीमा नहीं लागू होगी। स्कूटी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की टैप 5 छात्राओं को ही मिलेगी। सरकार सिर्फ स्कूटी ही नहीं देगी, बल्कि उसका बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और 4 लीटर पेट्रोल भी देगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला सशक्तीकरण और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शरानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी गई। यह योजना छात्राओं की उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी

योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की ड्राइपआउट दर को कम करना, उच्च शिक्षा में उनके अवधारण (रिटर्शन) को बढ़ाना, उच्च शिक्षण संस्थानों तक उनकी आवागमन सुविधा और गतिशीलता सुनिश्चित करना तथा सकल नामांकन अनुपात (लम्प) में वृद्धि करना है। इसके साथ ही छात्राओं में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तर प्रदेश की मूल निवासी उन छात्राओं को लाभ मिलेगा, जिन्होंने प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्वचालित पोषित महाविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। पात्र छात्राओं का चयन मेरिट के आधार पर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की टैप 5 प्रतिशत सूची से किया जाएगा।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार योजना में पेट्रोल चालित स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने यह निर्णय प्रदेश के दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर की बेहतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लिया है। स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे प्रारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। स्कूटी के पैकेज में केवल वाहन ही नहीं, बल्कि पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, आईएसआई मार्का हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल तथा सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी शामिल होगी, ताकि छात्राओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।

प्रदेश सरकार का कहना है कि इस योजना से उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ेगी, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। साथ ही यह योजना महिला सशक्तीकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का वर्ष 2026 का 3 अगस्त, 2026 (सोमवार) से आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुसूचक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।

राज्य विधानमंडल का द्वितीय सत्र 30 अप्रैल को आहूत किया गया था। उसी दिन विधानसभा एवं विधान परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी तथा 7 मई 2026 से सत्रावसान कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद-174 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। इसी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आगामी सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है।

लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसूचक अनुदानों की मांगें वि

धानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अलावा विगत सत्रावसान के बाद शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए प्रख्यापित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी सदन में प्रस्तुत कर पारित कराए जाएंगे।



साथ ही अन्य आवश्यक विधायी एवं शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सत्र की निर्धारित तिथि की सूचना सामान्यतः माननीय सदस्यों को सात दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाती है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 से प्रारंभ होगा। सत्र के दौरान अनुसूचक अनुदानों की मांगें, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट

बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के बस बेड़े को बढ़ाने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस पर कुल 425.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस निर्णय के

जाएगा।

नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर कुल 425.50 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। इसमें 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि शेष 25.50 करोड़

रहेगा। योगी सरकार का ये फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू होने वाले पर्यावरणीय मानकों को देखते हुए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

योगी सरकार इन इलेक्ट्रिक बसों के जरिए प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, पर्यटन व शहरी क्षेत्रों में यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित, आधुनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे डीजल आधारित बसों पर निर्भरता कम होगी, वायु प्रदूषण में कमी आएगी व पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

नई बसों के संचालन से परिवहन निगम के बेड़े का विस्तार होगा, जिससे चालकों, परिचालकों व तकनीकी रख-रखाव से जुड़े कुशल-अकुशल कर्मियों के लिए नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा बस संचालन से जुड़े ढाबों, रेस्टोरेट, अन्य यात्री सुविधाओं से संबंधित व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में 500 क्षमता वाले उच्च गुणवत्तापूर्ण महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 6,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यह भूमि हरिजन इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार

के नाम दर्ज है जिसे अब महिला कल्याण विभाग के पक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। इस छात्रावास का निर्माण शत-प्रतिशत राज्य सरकार के वित्त पोषण से किया जाएगा।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वाराणसी में 6000 वर्ग मीटर भूमि पर 500 क्षमता का एक छात्रावास बनाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। बजट में 7 छात्रावास बनाने का प्रावधान था, जिसमें से झांसी, आगरा, मेरठ और गोरखपुर के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। आज वाराणसी के लिए भी प्रस्ताव आज पास किया गया है।

प्रदेश में निजी, सरकारी और औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही महिला कार्यबल की जरूरतों को देखते हुए महिला कल्याण विभाग कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती छात्रावासों का निर्माण करा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सस्ती दरों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।

राज्य सरकार के अधीन कार्यरत महिला कल्याण विभाग इस योजना का संचालन श्रॉन-कॉमर्शियल, नो प्रॉफिट-नो लॉस सिद्धांत पर करेगा। इसी सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में छात्रावास निर्माण के लिए सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जा रही है।

ममता ने दिया टीएमसी के बागी गुट ने दिया एक महीने का अल्टीमेटम

नई दिल्ली।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़कर फिर से जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच लौटें। वहीं, उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से अपनी श्गलतियां श्स्वीकार करने की भी अपील की।

ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट की ओर से मेयो रोड पर आयोजित 21 जुलाई शहीद दिवस रैली में बोलेते हुए मदन मित्रा ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने कार्यकर्ताओं को

ने मुख्यमंत्री बनाया और न ही उन फिल्मी सितारों ने, जिन्हें

गांधारी की भूमिका निभा रही हैं। उनका कहना था कि वह श्मश्रुआवजाह देने का दावा

कहा, हम शहीदों को

आप इतना महत्व देती हैं। आपको लाखों तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने आपके लिए मेहनत की। कामरहाटी से विधायक मित्रा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक का समर्थन छोड़कर कार्यकर्ताओं के बीच लौटती हैं तो पार्टी उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेगी। महाभारत के पात्र गांधारी का जिक्र करते हुए मदन मित्रा ने कहा कि ममता बनर्जी अब

आपको लाखों तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने आपके लिए मेहनत की। कामरहाटी से विधायक मित्रा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक का समर्थन छोड़कर कार्यकर्ताओं के बीच लौटती हैं तो पार्टी उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेगी। महाभारत के पात्र गांधारी का जिक्र करते हुए मदन मित्रा ने कहा कि ममता बनर्जी अब

आप इतना महत्व देती हैं। आपको लाखों तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने आपके लिए मेहनत की। कामरहाटी से विधायक मित्रा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक का समर्थन छोड़कर कार्यकर्ताओं के बीच लौटती हैं तो पार्टी उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेगी। महाभारत के पात्र गांधारी का जिक्र करते हुए मदन मित्रा ने कहा कि ममता बनर्जी अब

आप इतना महत्व देती हैं। आपको लाखों तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने आपके लिए मेहनत की। कामरहाटी से विधायक मित्रा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक का समर्थन छोड़कर कार्यकर्ताओं के बीच लौटती हैं तो पार्टी उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेगी। महाभारत के पात्र गांधारी का जिक्र करते हुए मदन मित्रा ने कहा कि ममता बनर्जी अब



+ नगर पालिका परिषद अस्पताल, टांडा, रामपुर

(नगर पालिका परिषद टांडा, जनपद रामपुर)

योग्य एवं अनुभवी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित

निम्न पदों हेतु तत्काल आवश्यकता

• डॉक्टर
(MBBS / BAMS / BUMS)

• स्टाफ नर्स

• फार्मासिस्ट

• पैरामेडिकल स्टाफ

• कम्प्यूटर ऑपरेटर

• मेडिकल मार्केटिंग एगजीक्यूटिव

• फार्मसी मार्केटिंग एगजीक्यूटिव

• रिसेप्शनिस्ट

• अकाउंटेंट

• काउंसलर

वेतन

₹ 8,000 से ₹ 1,25,000

प्रतिमाह
(योग्यता, अनुभव एवं पद के अनुसार)

इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित पद हेतु अपना आवेदन एवं अद्यतन बायोडाटा (Resume) भेजें।
चयनित अभ्यर्थियों को Walk-in Interview, Google Meet Interview अथवा सीधी नियुक्ति हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

Walk-in Interview

Google Meet Interview

सीधी नियुक्ति

आवेदन भेजने हेतु ई-मेल :
npphtanda@gmail.com

संपर्क करें :
9871796100 / 8787045886

पता : नगर पालिका परिषद अस्पताल, टांडा, रामपुर, (उ.प्र.)

आग की सूचना पाकर पहुंची महापौर

लखनऊ। जवाहर भवन में आग लगने की जानकारी पाकर महापौर सुषमा खर्कवाल भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत तथा बचाव कार्यों की जानकारी ली। महापौर ने पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। कहा कि संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और सबसे सुखद बात यह है कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

गुणवत्तापूर्ण जल पर लविवि के विद्यार्थी करगे शोध

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पर शोध करेंगे। इसके लिए लविवि और मर्करी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता भी हुआ है। यह समझौता अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित है। कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मर्करी इंटरनेशनल के निदेशक दुर्गेश राय ने बताया कि उनकी कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पेयजल समाधान विकसित कर रही है। कुलपति प्रो. सैनी ने कहा कि इस साझेदारी से लविवि के विद्यार्थियों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर काम करने का अवसर मिलेगा और विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

पारंपरिक डिग्री से निकलकर एआई कौशल से जुड़ना जरूरी

लखनऊ। गुरुद्वारा आलमबाग के केंद्रीय सिंह सभा में सोमवार को शिक्षाविद डॉ. सतप्रीत सिंह का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. सतप्रीत सिंह ने कहा कि युवाओं को पारंपरिक डिग्री से आगे निकालकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता से जुड़ना जरूरी है। वहीं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि आज के दौर में सिर्फ डिग्रियां काफी नहीं हैं। गुरुद्वारा आलमबाग के अध्यक्ष सरदार निर्मल सिंह और महासचिव सरदार रतपाल सिंह गोल्डी ने कहा कि गुरुद्वारा परिसर में बन रहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में भी डॉ. सतप्रीत सिंह की विशेषज्ञता का लाभ लिया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के महासचिव सुरिंदर पाल सिंह बक्शी, राजेंद्र सिंह, हरजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

सीएचसी से कई चिकित्सक नदारद

लखनऊ। सोमवार को डिप्टी सीएम ने कैसरबाग स्थित रेडक्रॉस सीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी पंजीकरण, आयुष्मान भारत योजना, दवा वितरण और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। हाजिरी रजिस्टर की भी जांच की और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई चिकित्सक अनुपस्थित थे।

डिप्टी सीएम के अस्पताल पहुंचने की जानकारी पाकर सीएमओ डॉ. एनबी सिंह भी स्तर-1 के चिकित्साधिकारी डॉ. संदीप सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। सीएचसी अधीक्षक रितेश द्विवेदी अवकाश पर थे और उनके स्थान पर नियुक्त डॉ. अभिषेक मौर्य भी अनुपस्थित मिले। अस्पताल की व्यवस्था डॉ. अतुल संभाल रहे थे। डॉ. सुनंद भी बिना अवकाश प्रार्थनापत्र के अनुपस्थित पाई गई, जिस पर सीएमओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए।

डिप्टी सीएम ने आशा और एएनएम की तैनाती तथा आयुष्मान कार्ड से मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अ्धिकारियों को मरीज के प्रति किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी।

ट्रिपल आईटी के निदेशक बने प्रो. मनींद्र, कार्यभार संभाला

लखनऊ। आईआईटी कानपुर के निदेशक रहे प्रो. मनींद्र अग्रवाल को ट्रिपल आईटी लखनऊ का निदेशक बनाया गया है। उन्होंने प्रो. अरुण मोहन शेरी की जगह ली। इससे पहले ट्रिपल आईटी लखनऊ के निदेशक रहे प्रो. अरुण मोहन शेरी ने सोमवार को अपना पद छोड़ दिया। उन्हें आईआईएम शिलॉन्ग का निदेशक बनाया गया है।

प्रो. शेरी ने आईआईआईटी लखनऊ का नेतृत्व करने को सम्मान का विषय बताया। साथ ही विश्वास जताया कि प्रो. मनींद्र अग्रवाल के नेतृत्व में आईआईआईटी लखनऊ शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी विकास में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। प्रो. शेरी ने आईआईआईटी लखनऊ से जुड़ी प्रेरणादायी स्मृतियों को याद किया। उन्होंने संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

केजीएमयू के नेत्र रोग विभाग की दो सिस्टर इंचार्ज को नोटिस

लखनऊ। केजीएमयू के नेत्र रोग विभाग में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस मामले में जल्द ही दो सिस्टर इंचार्ज पर कार्रवाई हो सकती है। उपकुलसचिव प्रो. पवित्र रस्तोगी ने दोनों को नोटिस देकर तीन कार्य दिवस में जवाब मांगा है।

विभाग की जांच में पता चला कि जरूरी सामान और दवाइयां एचआरएफ स्टोर के बजाय बाहर से खरीदी जा रही थीं। सिस्टर इंचार्ज कंचन सिंह और सविता देवी को इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रो. पवित्र रस्तोगी के अनुसार, संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, कुलपति ने विभाग में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए 2025 संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई थी। इस एसओपी के हतत बाई की प्रमारी (सिस्टर को संबंधित रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना था कि ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं की खरीद एचआरएफ स्टोर से ही की जाए। किसी कारणवश बाहर से खरीद करनी पड़े तो स्रोत का सत्यापन शल्य प्रक्रिया से पहले करना था, मगर इस एसओपी का पालन नहीं किया गया।

केजीएमयू की कैंटीन में कॉकरोच मिलने पर शासन सरत

लखनऊ। केजीएमयू के शताब्दी भवन स्थित कैंटीन के फ्रीजर में केक पर कॉकरोच रेंगने के मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने केजीएमयू प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तलब की है। घटना 27 जून की है। इसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद अपर मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। शासन ने रिपोर्ट में कैंटीन की सफाई व्यवस्था की जानकारी मांगी है। खाद्य सामग्री के भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण और मरीजों व तीमारदारों को परोसे जाने वाले भोजन के मानकों की भी जानकारी मांगी है।

शासन ने ट्रॉमा सेंटर में निर्माण कार्य के चलते एंबुलेंस के फंसने और मरीजों को हो रही परेशानी



कैन्टीन में कॉकरोच मिलने की शिकायत

आवागमन में कोई बाधा न आए। शासन ने निर्माण एजेंसी और अस्पताल प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। शासन की सख्ती के बाद केजीएमयू प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू कर दी है।

जीएसटी सचल दल ने पकड़ी नौ बसें

लखनऊ। जीएसटी सचल दल ने “ऑपरेशन कवच” अभियान

पर गहन जांच की। पकड़ी गई बसों को राज्य कर विभाग

जोन-प्रथम के अपर आयुक्त मनोज कुमार विश्वकर्मा ने



लखनऊ में जीएसटी सचल दल की जांच

चलाकर नौ बसों को पकड़ा है। ये बसें यात्रियों के बजाय सामान ढो रही थीं। व्यापारियों द्वारा दिल्ली से कर चोरी करके यह माल लाया जा रहा था। टीम ने लखनऊ आने वाले सभी रास्तों

कार्यालय लाया गया है। यहां बरामद माल का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद इन बसों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य कर विभाग

बताया। जोन-दो के अपर आयुक्त अमरेश त्रिपाठी के साथ संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया गया। पांच सचल दल इकाइयों ने मिलकर नौ बसों को पकड़ा। इन बसों में बिना

परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आस्था बंसल, रमेश कुमार, श्याम सुंदर पाठक, खुश्बू, रवीश कुमार सिंह व श्याम वीर सिंह भी अभियान में शामिल रहे।

चार नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, 47 हजार करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को नई मजबूती देने वाले चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एवं गंगा

एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली दो लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए संशोधित एवं अंतिम रिव्हेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) को मंजूरी देने के साथ ही विध्य एक्सप्रेसवे और विध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक के अलाइनमेंट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे



ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मॉडल पर किया

जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,775.84 करोड़ रुपये है।

गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 90.84 किलोमीटर लंबे छह लेन (आठ लेन विस्तारणीय)

ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 7,488.74 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर कैबिनेट ने 12,264 करोड़ रुपये से अधिक की दो लिंक परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद दोनों परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता के चयन की निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। चयनित एजेंसी

को लगभग 36 माह में निर्माण कार्य पूरा करना होगा, जबकि इसके बाद पांच वर्षों तक अनुरक्षण (मेंटेनेंस) की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

योगी सरकार का उद्देश्य आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़कर एक मजबूत एक्सप्रेसवे ग्रिड तैयार करना है। इससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम होगी। साथ ही समय और ईंधन की बचत के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।कैबिनेट ने विध्य एक्सप्रेसवे के छह लेन (भविष्य में आठ लेन विस्तारणीय) ग्रीनफील्ड

प्रशिक्षण पूरा कर जेल अधिकारियों ने दी सलामी

लखनऊ। आलमबाग स्थित डॉ. संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान (जेल ट्रेनिंग स्कूल) में सोमवार को कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्रशिक्षण पूरा कर चुके जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की पासिंग आउट



परेड की सलामी ली। प्रशिक्षण में सर्वोच्च प्रशिक्षणार्थी का अवॉर्ड

अधिकारी संवर्ग में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जेल अधीक्षक टामन और जेल वार्डर संवर्ग में बागपत में तैनात जेल वार्डर अतुल यादव को दिया गया। मंत्री ने अव्वल प्रदर्शन करने वाले 31 प्रशिक्षणार्थियों को स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

महानिदेशक कारागार पीसी मीणा ने ईमानदारी व सेवा भाव के साथ नौकरी करने के लिए कहा। संस्थान के निदेशक डॉ. रामधनी, आगरा रेंज व मुख्यालय डीआईजी प्रेमनाथ पांडेय, अयोध्या रेंज के जेल डीआईजी शैलेन्द्र मैत्रेय व डीआईजी सुभाष चंद्र शाक्य व छत्तीसगढ़ के सहायक महानिरीक्षक अनित शांडिल्य समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।

प्रदेश के इन 63 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी

लखनऊ।

यूपी में मानसूनी पूरी तरह से सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। खासकर बरेली, लखीमपुर खीरी, रामपुर, शाहजहांपुर जैसे जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। लगातार बारिश से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार के लिए प्रदेश के 18 जिले में अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 45 अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। कुल मिलाकर ऐसे 63 जिले हैं जहां बारिश या अति बारिश हो सकती है। साथ ही लगभग 60 जिलों में गरज चमक और वज्रपात की भी चेतावनी है।

सोमवार को तराई के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। बरेली में सर्वाधिक 174 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद लखीमपुर खीरी में 160 मिमी, रामपुर में 152 मिमी और शाहजहांपुर में 150.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात की भी स्थिति बन सकती है।

उत्तर प्रदेश में जुलाई के दौरान मानसूनी बारिश ने कमी पूरी कर ली है। 20 जुलाई तक प्रदेश में 160.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि इस अवधि का सामान्य आंकड़ा 170.3 मिमी है। यानी अब तक केवल छह प्रतिशत कम बारिश हुई है, जो मौसम विभाग के अनुसार सामान्य श्रेणी में आती है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में मानसून की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है।

बांदा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी व आस के क्षेत्र।

मार्ग को भी मंजूरी दी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 26,315 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के तहत प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। इसके अलावा विध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक (विकल्प-1) को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। लगभग 9,039 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को आपस में जोड़ेगी।

विश्व हिंदू परिषद से ही होगा राम मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव, बैठक में खाली पदों पर भी होगा फैसला

लखनऊ। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में संगठनात्मक ढांचे और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव के चयन के साथ ही लंबे समय से रिक्त पड़े दो अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने पर भी निर्णय होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया महासचिव विश्व हिंदू परिषद का ही होगा, यह लगभग तय हो चुका है।

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में सामने आए चढ़ावा चोरी प्रकरण और उसके बाद हुई जांच के मद्देनजर ट्रस्ट और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा

रहा है। इसी क्रम में नई कार्यप्रणाली, जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत मंथन होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद खाली पड़ पदों पर नए नामों की घोषणा की जाएगी। इसके लिए बैठक दो सत्रों में आयोजित की गई है। पहले सत्र में दोपहर तीन बजे से खाली पदों के चयन पर मंथन होगा। दूसरे सत्र में दोपहर चार बजे से बैठक में अन्य विषयों पर मंथन होगा।

नए महासचिव की नियुक्ति को ट्रस्ट के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में खाली पड़े दो अन्य पदों पर भी नियुक्ति किए जाने की उम्मीद है। बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से रिक्त हुए पद पर उनके पुत्र राज परिवार के सदस्य व साहित्यकार यतींद्र मिश्र का भी चयन होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ट्रस्ट में अयोध्या के किसी एक संत को भी स्थान दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बैठक में मंदिर के चढ़ावे की गणना, लेखा प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को लेकर नई व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी।

— राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि बैठक दोपहर तीन बजे मणिराम दास की छावनी में होगी। बैठक में जो भी निर्णय होगा वह सभी

सदस्यों को मान्य होगा। बैठक में राम मंदिर में नोटो की कारउटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा एसआईटी जांच पर भी चर्चा होगी। बताया कि राम मंदिर में इस समय पूजा परंपरा का निर्वहन रामानंदीय परंपरा के अनुरूप बेहतर ढंग से किया जा रहा है। व्यवस्थाओं की लगातार मानीटरिंग ट्रस्ट की ओर से की जा रही है।

बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का अयोध्या आगमन शुरू हो चुका है। मंगलवार की देर शाम युगपुरुष परमानंद व जगद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती अयोध्या पहुंच गए, जबकि कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि बुधवार की सुबह

11 बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरण बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ विहिप के पदाधिाकारियों की भी जुटान शुरू हो गई है। विहिप के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी, वरिष्ठ संरक्षक दिनेश चंद्र अयोध्या पहुंच चुके हैं।



मयुरा में 25 लाख की टप्पेबाजीरु कार रुकवाकर नोटों से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश -सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचे सीओ रिफाइनरी

(मथुरा)(ए.के.शर्मा)

थाना हाईवे क्षेत्र में सोमवार को दिनदहाड़े टप्पेबाजी की बड़ी वारदात सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने प्लाईवुड कारोबारी के कर्मचारियों को झांसे में लेकर कार में रखा 25 लाख रुपये से भरा बैग पार कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना हाईवे पुलिस और सीओ रिफाइनरी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा जांच शुरू कर दी।



चंद्रिका प्लाईवुड के स्वामी नीलेश अग्रवाल ने बताया कि उनकी बेटी का विवाह होने वाला है। इसी सिलसिले में उनके कर्मचारी 25 लाख रुपये लेकर गोविंद नगर निवासी उनके साढ़ू सुनील बंसल के यहां जा रहे थे। कार में चालक रमेश के साथ कर्मचारी सुनील और मेघश्याम मौजूद थे।

नीलेश अग्रवाल के अनुसार, जैसे ही उनकी कार हाईवे क्षेत्र में राधा वैली के पास पहुंची, तभी बाइक सवार कुछ युवकों ने चालक से कहा कि गाड़ी के इंजन से ऑयल फैल रहा है। इस पर चालक ने कार रोक दी और नीचे उतरकर बोनट खोलकर इंजन की जांच करने लगा। इसी दौरान कार में आगे बैठे कर्मचारी का ध्यान भटकते ही बदमाश नोटों से भरा बैग उठाकर मौके से फरार हो गए।

घटना का एहसास होते ही चालक और कर्मचारियों ने शोर मचाया तथा तत्काल इसकी सूचना नीलेश अग्रवाल को दी। सूचना मिलने पर नीलेश अग्रवाल और उनके अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना हाईवे पुलिस के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चालक रमेश तथा कर्मचारी सुनील व मेघश्याम से विस्तृत पूछताछ की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके।

वही इस घटना के संबंध मे सीओ रिफाइनरी प्रवीण कुमार तिवारी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला टप्पेबाजी का प्रतीत हो रहा है। बदमाशों ने पहले वाहन में तकनीकी खराबी होने का भ्रम पैदा किया और फिर चालक व कर्मचारियों का ध्यान भटकाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आसपास के मार्गों के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नगर आयुक्त ने संभव संतुष्टि एवं समृद्धि के तहत शिकायतों को सुना -शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित को त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु किया निर्देशित (मथुरा)

नगर आयुक्त ओजस्वी राज

मथुरा वृंदावन नगर निगम को प्रदेश की सबसे खूबसूरत निगम बनाने के संकल्प मे संकल्पित हैं। उनका प्रयास हैं निगम पूरी तरह से डिजिटल हो जिससे सब कुछ सामने हो। वही नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने संभव संतुष्टि एवं समृद्धि के अंतर्गत जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया, जिसके दृष्टिगत भूतेश्वर स्थित नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने जनसुनवाई की वही सिटी जोन जनरल गंज कार्यालय में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार और



वृंदावन जोनल कार्यालय में अपर नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश पाठक ने जनसुनवाई की। नगर आयुक्त ने सभी शिकायत कर्ताओं की शिकायत का संज्ञान लेकर सम्बन्धित अधिकारी को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनसुनवाई के दौरान भूतेश्वर जोन में कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 02 अतिक्रमण, 02 जलकल, 01 लाइट, 05 सफाई एवं 05 टैक्स से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें से 3 सिविल विभाग, 01 लाइट विभाग एवं 01 आवारा कुत्ता पकड़ने में कुल 05 शिकायत का निस्तारण करा दिया गया है। सिटी जोन में 03 शिकायत प्राप्त हुई। 02 सफाई एवं 01 टैक्स के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। वृंदावन जोन में कुल 10 शिकायत प्राप्त हुई है। जिनमें से 05 जलकल विभाग, 02 निर्माण, 01 नामांतरण एवं 02 अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुई शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कराया जाये। जनसुनवाई में अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह, सहायक नगर आयुक्त नीरज शर्मा, सहायक नगर अनुज कौशिक, मुख्य अभियंता निर्माण संजय सिंह, महाप्रबंधक जल मोहम्मद अनवर ख्वाजा, अधिशासी अभियंता निर्माण अमरेंद्र गौतम, सहायक अभियंता जल हेमेंद्र गौतम, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. रामगोपाल आदि उपस्थित रहे।

कानपुर। कानपुर जिले में सामने आए 3200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित अवैध लेनदेन मामले में मुख्य आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले के मुख्य अभियुक्त महफूज उर्फ पप्पू छुरी के बेटे और 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी फैज आलम की दो अलग-अलग जमानत अर्जियों को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया है।

यह महत्वपूर्ण फैसला अपर जिला जज (अष्टम) विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने सुनवाई के बाद सुनाया है। आरोपी फैज आलम पर लोगों के फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर बैंक खाते खुलवाने और उनके जरिए करोड़ों रुपये का संधिध लेनदेन करने के गंभीर आरोप दर्ज हैं।

अदालत में मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय

अधिवक्ता ने बताया कि इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर चक्रेरी के स्क्रेप कारोबारी अजय शुक्ला और जाजमऊ निवासी मोहम्मद आजम ने अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दोनों पीड़ितों का गंभीर आरोप था कि आरोपी फैज आलम और उसके पिता ने मिलकर उनके महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया। पीड़ितों की जानकारी के बिना फर्जी तरीके से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए गए और फिर उन बैंक खातों के जरिए लाखों-करोड़ों रुपये का अवैध लेनदेन कर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के खेल को अंजाम दिया गया।

पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल

जब पीड़ितों को उनके नाम पर हुए इस विशालकाय फर्जीवाड़े

प्रयागराज के विक्रम मोंट्रोज ने बरलीवुड में बजाई सफलता की धुन

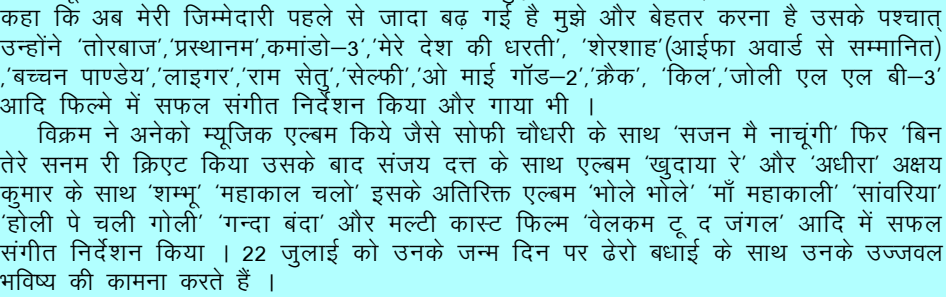
प्रयागराज निवासी विक्रम मोंट्रोज ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर बॉलीवुड (मुंबई) में एक अलग पहचान बनाई है। प्रयागराज से मायानगरी मुंबई तक का उनका सफर संघर्ष, समर्पण और संगीत के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है।

विक्रम 21 वर्ष पहले मायानगरी मुंबई पहुंचे थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने विज्ञापन और छोटे प्रोजेक्ट्स से शुरुआत की। धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें बड़े बेनर की फिल्मों में काम करने का अवसर मिला।

विक्रम ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू’ से की। इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त (संजू बाबा) ने उन्हें मौका दिलाया, और यही अवसर उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। फिल्म के गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और विक्रम को संगीत जगत में पहचान दिलाई।

विक्रम ने बेहद, अदभुत संगीत निर्देशन किया ‘संजू ’ जैसी फिल्मों में । उनकी रचनाओं में प्रयागराज की मिट्टी की सादगी और मुंबई की आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाई देता है। 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने वह मुकाम हासिल किया, जिसकी कल्पना कई आदि फिल्मे में सफल संगीत निर्देशन किया और गाया भी।

विक्रम ने अनेको न्यूजिक एल्बम किये जैसे सोफी चौधरी के साथ ‘सजन मै नाचूंगी’ फिर ‘बिन तेरे सनम री क्रिए्ट किया उसके बाद संजय दत्त के साथ एल्बम ‘खुदाया रे’ और ‘अधीरा’ अक्षय कुमार के साथ ‘शम्शू’ ‘महाकाल चलो’ इसके अतिरिक्त एल्बम ‘भोले भोले’ ‘मॉ महाकाली’ ‘सांवरिया’ ‘होली पे चली गोली’ ‘गन्दा बंदा’ और मल्टी कास्ट फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ आदि में सफल संगीत निर्देशन किया । 22 जुलाई को उनके जन्म दिन पर ढ़ेरो बधाई के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं ।



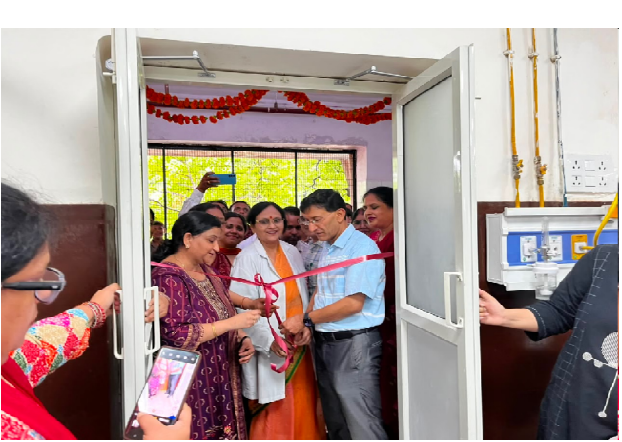
हैलट जच्चा-बच्चा अस्पताल में शुरु हुआ 20 बेड का HDU वार्ड

कानपुर।

कानपुर के प्रसिद्ध गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट जच्चा–बच्चा अस्पताल में महिला स्वास्थ्य और प्रसूति सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अस्पताल परिसर में गंभीर हालत में आने वाली प्रसूताओं के त्वरित और उच्च स्तरीय इलाज के लिए 20 बेड वाले विशेष हाई डिपेंडेंसी यूनिट की विधिवत शुरुआत कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के शुरु होने से अब कानपुर मंडल और आसपास के जिलों से आने वाली गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं को सही समय पर बेहतर और अत्याधुनिक चिकित्सीय देखभाल मिल सकेगी, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी।

अस्पताल प्रशासन द्वारा शुरु किए गए इस नव निर्मित एचडीयू

(HDU) वार्ड को पूरी तरह से आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया गया है। 20 बेड वाले



इस पूरे वार्ड में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे सांस लेने में तकलीफ का सामना कर रही प्रसूताओं को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सकेगा।

इसके अलावा, प्रत्येक बेड पर मरीजों के वाइटल्स (ब्लड

प्रेसर, पल्स रेट और ऑक्सीजन

किसी भी गंभीर स्थिति से तत्काल

निपट्टा जा सके।

गंभीर प्रसूताओं की देखभाल के लिए एचडीयू वार्ड में विशेष रूप से प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टरों की तैनाती की गई है। यह मेडिकल टीम 24 घंटे शिफ्ट के हिसाब से मरीजों की स्थिति पर निरंतर नजर रखेगी। डॉक्टरों के अनुसार, कई बार प्रसव के समय या उसके ठीक बाद महिलाओं का ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है या भारी रक्तस्राव की समस्या खड़ी हो जाती है।

ऐसे अति गंभीर मामलों में इस यूनिट के जरिए समय रहते मरीज को गहन चिकित्सा सुविध ा मिल सकेगी। इस नई सुविधा के शुरु होने से हैलट अस्पताल में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी और गंभीर मरीजों को निजी अस्पतालों के महंगे चक्कर काटने से राहत मिलेगी।

‘दीदी, मुझे कुछ हो जाए तो -, आत्मदाह करने वाले महेश की मौत

कानपुर।

कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में पत्नी से विवाद के बाद थाने के भीतर खुद को आग लगाने वाले मजदूर महेश (38) की रविवार देर रात इलाज के दौरान लखनऊ के अस्पताल में मौत हो गई। महेश के परिजनों ने अब उसके ससुरालवालों पर पिटाई का आरोप लगाया है।

कहना है कि पत्नी से विवाद और ससुरालियों की पिटाई से आहत होकर ही महेश ने जान दी है। सोमवार को महेश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल में भर्ती महेश ससुरालवालों पर आरोप लगा रहा है। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह का कहना है कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

मिलेगी तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मामले में वायरल किसी भी वीडियो की अमर उजाला पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि बीती 14 जुलाई को थाना क्षेत्र के फुफवार राजथोक गांव निवासी

और आयकर विभाग के नोटिस का पता चला, तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फैज आलम लगातार फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

बाद में पुलिस की विशेष टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी फैज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद फैज आलम की ओर से दोनों दर्ज मुकदमों में जमानत के लिए अपर जिला जज (अष्टम) की अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी।

कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता, 3200 करोड़ रुपये के विशालकाय आर्थिक साम्राज्य और फर्जीवाड़े के साक्ष्यों को मजबूती से अदालत

के सामने रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों का गहन अनुशीलन करने के बाद माना कि आरोपी पर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं।

इसके बाद अपर जिला जज अष्टम विजय कुमार गुप्ता ने आरोपी फैज आलम की दोनों जमानत याचिकाओं को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब आरोपी को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।



नालियां जाम तो सड़कों पर भरा पानी, जिम्मेदार बने अनजान

कानपुर। कानपुर के नरवल तहसील क्षेत्र में मानसून की हल्की सी बारिश के बाद ही जगह–जगह जलभराव की समस्या सिर उठाने लगी है। नालियों की सफाई न होने और निकासी की अव्यवस्था के कारण गांवों की गलियों और मुख्य मार्गों पर पानी भर गया है। इससे लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया है।

विकासखंड सरसोल के ग्राम नौगवा गौतम के ग्रामीण रवि सैनी ने बताया कि बारिश के बाद गली में घुटनों तक पानी भर गया है। स्कूली बच्चे जूते हाथ में लेकर पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि यह समस्या सिर्फ बारिश की नहीं है, बल्कि पूरे साल इस गली की यही दुर्दशा बनी रहती है।

नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण घरों के बाहर हमेशा पानी और कीचड़ जमा रहता है। यह गांव का मुख्य मार्ग

भी है। इसलिए दिनभर लोगों का आना–जाना लगा रहता है। फिसलन भर रास्ते पर कई लोग कीचड़ में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद न तो सफाईकर्मों ध्यान दे रहे हैं और न ही संबंधित विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। ग्रामीण रवि सैनी, मनोज गुप्ता,

अनिल सैनी, छोटेलाल बेरिया,

विनोद सविता, संजय बेरियान

सहित तमाम ग्रामीणों ने जिला

प्रशासन और पंचायत विभाग

से मांग की है कि बरसात से

पहले नालियों की सफाई और

जल निकासी की उचित

व्यवस्था की जाए, वरना

बीमारियां फैलने और हादसों

का खतरा बढ़ जाएगा।

सधन चेकिंग के बाद फर्जी पतकार जाएगे जेल - डी एम

एसपी स्तर पर होगी फर्जी पत्रकारों की जाँच तभी बनेंगे पास, एसएसपी ब्रज प्रेम कलब द्वारा डीएम,एसएसपी को दिया गया जापन देकर फर्जी पत्रकारों के के विरुद्ध विशेष अभियान की मांग

(मथुरा)

ब्रज प्रेम कलब द्वारा मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी को एक जापन देकर फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की मांग की गई

पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी श्री चंद्रप्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक कुमार ने कहा कि जिला सूचनाअधिकारी के माध्यम से एवं पुलिस की तरफ से एसपी स्तर से एवं गुप्तचर विभाग से अलग–अलग स्तर पर जांच होगी अगर

कोई अपराधी पत्रकार बनकर घूम रहा है तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही होगी

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही को लेकर की गई महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद ब्रज प्रेम कलब द्वारा फर्जी पत्रकारों एवं फ़ेसब लिखे फर्जी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया

बृज प्रेम कलब के अध्यक्ष डॉ कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने कहा कि न्यायालय की टिप्पणी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखने के लिए फर्जी और गैर–जिम्मेदार तत्त्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज मोबाइल और माइक्रोफोन लेकर कोई भी स्वयं को पत्रकार बताने लगता है, जबकि उसके पास न तो पत्रकारिता का प्रशिक्षण होता है और न ही समाज के प्रति जवाबदेही। उन्होंने कहा कि समिति का अभियान वास्तविक पत्रकारों के विरुद्ध नहीं, बल्कि पत्रकारिता का आड़ में गलत गतिविधियां करने वाले फर्जी पत्रकारों तथा अवैध रूप से फ़ेसब लिखकर चलाए जा रहे वाहनों के खिलाफ है।

उन्होंने बताया कि अंतिम सप्ताह जुलाई से अभियान का शुभारंभ शुरू कराया जाएगा। जिले के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी से मिल कर विशेष अभियान पूरे बृज क्षेत्र में चलाया जाएगा

उन्होंने बृज क्षेत्र के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों से इस अभियान में बंद–चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता, समाज के विश्वास और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा की रक्षा के लिए सभी जिम्मेदार पत्रकारों को एकजुट होना होगा।

यह अभियान फर्जी पत्रकारों और प्रेस का दुरुपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध होगा यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पत्रकारिता की साख बचाने का जन–जागरण अभियान की तरह होगा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान पूरे बृज क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश देगा

आज मथुरा जिला मुख्यालय पर सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल साइट युट्युबर्स के अच्छे और सम्मानित पत्रकार जो समाज और राष्ट्र की सेवा करते हैं जनता की आवाज बनते हैं वह सभी पत्रकारों ने बड़ी संख्या में एक साथ मिलकर के जिलाधिकारी और एसएसपी से मिलकर के एक ज्ञापन दिया ,जिसमें फर्जी पत्रकारों पर रोक लगे समाज को लूटने वाले एवं संस्थानों में जाकर ब्लैकमेलिंग कर चौथ वसूली करने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सके

जो अच्छे और सच्चे कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है उनकी छवि को उनकी आन बान शान को प्रभावित करते हैं ऐसे अपराधी माफिया लुटेरे जो फर्जी पत्रकार बनकर के घूम रहे हैं उनको बेनकाब किया जा सके उनकी जांच कर के उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराई जा सके जिससे पत्रकारों की इज्जत को बचाया जाए पत्रकारों द्वारा जिला प्रशासन को बताया गया कि हम सब मिलकर के ब्राजभूमि को अपराधी ब्लैकमेलों से जो पत्रकारिता के भेप में छुपे हैं उनसे बचे अपने धर्म स्थलों से जो बचाए आने वाले वीआईपी की सुरक्षा को खतरा होने से बचाये

फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध ब्रजभूमि से एक वृहद अभियान की शुरुआत हो, इस पुनीत कार्य में अपनी आहुति दें सभी सच्चे और अच्छे पत्रकार साथ हैं

जैसे तहसील में लेखपाल होता है अपने नीचे कर फर्जी लेखपालों को रखता है ऐसे कई लोग हैं जो अपने नीचे अपराधि ायों को संरक्षण देते हैं और उनसे चौथ वसूली और विज्ञापन के नाम संस्थान में लूटमार करवाते हैं जो उचित नहीं हैं।

क्या फिर होगी धामी सरकार की सत्ता में वापसी

प्रभासाक्षी के साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में इस सप्ताह हमने आगे की राजनीति और होने वाले चुनावों पर चर्चा की। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। नीरज कुमार दुबे ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजे के बाद भाजपा गदगद है। बीजेपी का उत्साह चरम पर है और आने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव में भी बीजेपी के इस उत्साह को हम देख सकते हैं। बीजेपी के लिये चुनौतीपूर्ण रहने वाली है क्योंकि 2027 में कई ऐसे राज्यों में चुनाव है जहां बीजेपी सत्ता में है और वहां पर सत्ता बनाए रखने की चुनौती उसके पास रहने वाली है। प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे ने यह भी कहा कि

बीजेपी एक चुनावी मिशन की तरह काम करती है। एक राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद वह अपने अगले लक्ष्य को लेकर तैयारियां शुरू कर देती है। उन्होंने इस दावा किया कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों के लिए चुनावी रणनीति बनाने की शुरुआत कर चुकी है और वहां पर कार्यकर्ताओं कोई कलेक्शन देश देने की कोशिश की जा रही है।

नीरज कुमार दुबे ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालते ही चुनावी वादों पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाने तो शुरू कर ही दिये हैं साथ ही राज्य की राजनीति और प्रशासन में तेज बदलावों का दौर भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने

मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें राज्य की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उनके गढ़ में पराजित कर सत्ता तक पहुंचे सुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के केवल 48 घंटे के भीतर लगभग डेढ़ दर्जन बड़े निर्णयों की घोषणा कर यह संकेत दे दिया कि नई सरकार प्रशासनिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर व्यापक बदलाव चाहती है।

नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी। कोलकाता के रेंड रोड क्षेत्र में सार्वजनिक नमाज पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया गया है। सरकार ने पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में



क्या है सोनम वांगचुक का असली सच?

यह कहानी उस अपराजेय डोगरा सेनापति की है, जिसने उत्तर के दुर्जय शिखरों और बर्फीली वादियों को चीरकर भारत की सीमाओं का ऐसा विस्तार किया जिसकी मिसाल इतिहास में विरली ही मिलती है। कहलूर रियासत के एक साधारण से गाँव में जन्मे और जमीन के पारिवारिक विवाद के कारण अपना घर छोड़ने वाले जोरावर सिंह कहलुरिया ने हरिद्वार के मैदानों से लेकर जम्मू के दुर्गम क्षेत्रों तक न सिर्फ युद्ध की कलाएँ सीखीं, बल्कि महाराजा रणजीत सिंह, राजा संसार चंद और डोगरा राजा गुलाब सिंह जैसे महान शासकों के भरोसे को जीतकर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। भीमगढ़ किले की कमान से लेकर किश्नवाड़ की गवर्नरशिप तक का सफर तय करने वाले इस वीर की तलवार ने साल 1834 में

जब लद्दाख के बर्फीले रास्तों का रुख किया, तो उसने तिब्बत से अफगानिस्तान तक फेले व्यापारिक मार्गों की तकदीर और डोगरा साम्राज्य की सीमाओं का इतिहास हमेशा-हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। लद्दाख आधिाकारिक तौर पर हमेशा के लिए जम्मू की डोगरा रियासत का हिस्सा बन गया और फिर जम्मू कश्मीर के साथ ही सन 47 में लद्दाख भारत का हिस्सा बना। कट टू आजादी के 72 साल बाद तारीख 5 अगस्त 2019 जगह देश की संसद जहां देश भर से चुनकर आए जनता के प्रतिनिधि 1 बैठे हैं लेकिन एक सांसद मोहोदय खड़े हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह सफेद कुर्ता और गाढ़े भूरे रंग की सदरों। हाथ में कागजों का पुलिंदा है। जिनमें अलग-अलग पन्नों पर स्टिकी

नोट्स चसपा थे। इन कागजों को हाथ में लिए अमित शाह जम्मू कश्मीर से जुड़े दो बिल और दो प्रस्ताव पेश करते हैं। यह बिल और प्रस्ताव पास होते ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। साथ ही जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया जाता है। दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। पहला जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ, और दूसरा लद्दाख बगैर वि्धानसभा के। जो लद्दाख सेनाओं की लड़ाई के बाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया गया था, उसे एक बार फिर कश्मीर से अलग कर दिया गया। इस फैसले को लद्दाख में खुशखबरी की तरह सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेशन का पहला बयान आया लद्दाख के एक इंजीनियर, साइंटिस्ट,

शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से जिन्हें हिंदुस्तान ने उनके असली नाम से कम और आमिर खान की फिल्म से मिले नाम से ज्यादा जाना। श्री इंडियट्स वाले फुनसुक बांगरू। असली नाम सोनम वांगचुक। वांगचुक ने 5 अगस्त 2019 की रात सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद। लद्दाख नरेंद्र मोदी और पीएमओ का धन्यवाद करता है और उन्होंने लद्दाख के लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा किया। ठीक 30 साल पहले अगस्त 1989 में लद्दाख के नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में मदद की। लेकिन बहुत जल्द सोनम वांगचुक का शुक्राना अंदाज बदल

जाता है और वह कहने लगते हैं कि इससे तो बेहतर था कि हम जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा रहते। अब सोनम वांगचुक एक बार फिर से चर्चा में हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अब अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश का हवाला देते हुए 18 जुलाई को उन्हें जबरन सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। अस्पताल में उन्होंने ड्रिप या मुंह से कोई भी तरल पदार्थ लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनका अनशन जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपना अनशन खत्म करने के लिए तीन शर्तें रखीं। सोनम वांगचुक ने जो शर्तें रखी हैं उनमें कहा गया है कि सरकार प्रश्नपत्र लीक होने जैसी घटनाओं समेत शिक्षा व्यवस्था की र्हाल की नाकामियों का जिम्मा लेती है या फिर राजनीतिक दल संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा देते हैं या फिर अलग-अलग दलों के सांसद और नेता अस्पताल आकर उनसे मिलकर आश्वासन देते हैं तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। ऐसे में आएए जानते हैं कि सोनम वांगचुक आखिर है कौन? टाइम मैगजीन ने सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा था? वांगचुक को किस काम के लिए रमन मैसैस अवाइं मिला था? सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया था?

क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 नाम से एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सोनम वांगचुक का भी नाम शामिल था। मैगजीन ने नाम के साथ सोनम वांगचुक का परिचय देते हुए जो कहा वह पढ़ने लायक है। वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले महीने उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने का काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं।

सोनम वांगचुक आज देश भर में चर्चा का नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस परिवार से सोनम वांगचुक आते हैं उस परिवार का आंदोलन और लद्दाख की राजनीति से रिश्ता आज का नहीं बल्कि 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज जिस तरह सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ठीक उसी तरह 42 साल पहले उनके पिता भी अनशन पर बैठे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद दिल्ली से लेह पहुंच गई थी और अपने हाथों से उनका अनशन तुड़वाया था। सोनम वांगचुक के पिता का नाम था सोनम वांग्याल। सोनम वांग्याल सिर्फ एक राजनेता नहीं थे बल्कि लद्दाख की पहचान और अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। 1975 में वे जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने और बाद में राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। यही हर दौर था जब लद्दाख के लोगों को लगता था कि उनकी आवाज श्रीनगर की राजनीति में दब जाती है। लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले ताकि शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। यही मांग आगे चलकर एक बड़े जन आंदोलन में बदल गई। साल था 1984। सोनम वांग्याल ने लद्दाख के लोगों के अधिकारों की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांग साफ थी कि लद्दाख को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। अनशन लंबा खिसाने लगा। जैसे-जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, मामला दिल्ली तक पहुंच गया। उस समय देश की प्र्धानमंत्री श्री इंदिरा गांधी। रिपोर्टों के मुताबिक मामला इतना गंभीर हो गया कि इंदिरा गांधी खुद लेह पहुंचीं। सोनम बांग्याल से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया।

भारत के उत्तरी कोने पर बसा लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन साल 2019 से पहले तक वह जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था।

सम्पादकीय

संस्कृत के 230 श्लोकों में दो हजार साल की पान की परंपरा

16वीं सदी में सैयद उसमान ने अपनी रचना चित्रावती में पान को बंगाल की नियामत माना है। वहीं फ्रांसीसी यात्री बर्नियर लिखते हैं कि पान को चूने व कई खुशबूदार जड़ी-बूटियों से तैयार किया जाता था। पैंजारा से पान के बीड़े की भला बयाा औकात होती है, लेकिन जब यह बीड़ा उठाना पड़ जाए, तो बीरता और शौर्य की गाथा लिख दी जाती है।

तारीख के जर्द पन्नों में पान की कितनी ही दास्तानें छिपी हैं। पान आम भी है और खास भी। पान के बारे में जिक्र सबसे पहले चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। पान शब्द संस्कृत के पर्ण से आया है, जिसका अर्थ होता है पत्ता। पान की शान के तो कहने ही क्या। एक मुगल शहजादी को तो पान खर्च के नाम पर सूरत के समूद्ध बंदरगाह से होने वाली लाखों की आमदनी ही सौंप दी गई।

तुलसीदास ने रामचरितमानस में पान का जिक्र किया है, जब राजा जनक पान के बीड़े से राजा दशरथ का स्वागत करते हैं। वहीं मलिक मोहम्मद जायसी ने पदमावत में पान की महिमा का बखान किया है। जब पदिमनी से मिलने राजा रतन सेन पहुंचे, तो उनका स्वागत पान से ही किया गया। संस्कृत ग्रंथ तांबूल मंजरी तो जैसे पान का एन्साइक्लोपीडिया है। इस ग्रंथ के 230 श्लोकों में दो हजार साल की पान की परंपरा को समेटा गया है। 1334 से 1341 ईस्वी तक भारत में रहे मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने लिखा है कि पान को अंगूरों की तरह उगया जाता है। बतूता लिखते हैं कि दिल्ली के सुलतान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रात के भोजन के बाद सभी को पान दिया जाता था। वहीं 14वीं सदी के महान जनकवि अमीर खुसरो ने अपनी एक मुकुरी में लिखा है, मुंह आए तो रस बरसावे, तन-मन की सब तपन बुझावे, अधर लगावत रस की खान, क्यों सखि साजन? न सखि, पान।

इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं, बादशाह अकबर के लिए आगम में खास तौर पर पान उगाए जाते थे। आइन ए अकबरी में उन्होंने लिखा है, पान खाकर भूख मिट जाती है, तो कभी पान खाने से भूख लगने लगती है। 16वीं सदी में सैयद उसमान ने अपनी रचना चित्रावती में पान को बंगाल की नियामत माना है। वहीं फ्रांसीसी यात्री बर्नियर लिखते हैं कि पान को चूने और कई खुशबूदार जड़ी-बूटियों से तैयार किया जाता था। वेनिस से 1656 में सूरत बंदरगाह पहुंचे इतालवी यात्री निकोलो मनुची का विवरण तो बेहद दिलचस्प है। जलपोत से उतरते ही हर किसी को मुंह से लाल रंग की पीक छोड़ते देख उन्हें लगा यह खून है और यहां महामारी फैली हुई है। हालांकि बाद में उनकी भ्रांति दूर हो गई। राजपूतों में पान शौर्य और वीरता का प्रतीक था। पान का बीड़ा उठाने का मतलब था अस्मंभ चुनौती को भी स्वीकार कर लेना। यानी पान एक और मिजाज हजारा।

अपने भीतर उतरना ब्रह्म की याता है, स्वयं से संवाद करना प्रभावी सूत्र

मनुष्य सदियों से आकाश की ओर देखता आया है। उसने तारों को गिना, ग्रहों की गति को समझा, दूरबीन बनाई व ब्रह्मांड के रहस्य कोनों तक अपनी नजर पहुंचाई। यह खोज बताती है कि हम कितने विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। किंतु यदि हमारी यात्रा केवल बाहर ही बाहर रहे, तो वह अधूरी रह जाएगी। एक समय ऐसा आता है, जब मनुष्य समझने लगता है कि ब्रह्मांड को देखने वाला भी उसी ब्रह्मांड का एक अंश है।

जो आंख तारों को देख रही है, वह भी उन्हीं प्राकृतिक नियमों का परिणाम है, जिन्हें वह समझना चाहती है। जो बुद्धि आकाशगंगाओं का अध्ययन कर रही है, वही स्वयं प्रकृति की एक अभिव्यक्ति है। तब प्रश्न बदल जाता है। तब हम केवल यह नहीं पूछते कि ब्रह्मांड क्या है। हम यह भी पूछते हैं कि वह चेतना क्या है, जो यह प्रश्न पूछ रही है। और यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। जब कोई वैज्ञानिक किसी तारे का अध्ययन करता है, तो वह प्रकाश, ऊर्जा और गुरुत्व के नियमों को समझता है।

जब वही वैज्ञानिक अपने भीतर झांकता है, तो वह आशा, प्रेम, जिज्ञासा, भय और मौन को पहचानता है। दोनों यात्राएं भिन्न प्रतीत होती हैं, किंतु दोनों का उद्देश्य एक ही है—सत्य की तलाश। मनुष्य सोचता है कि वह एक छोटा-सा प्राणी है, जो विशाल संसार को बाहर से देख रहा है। परंतु हम बाहर खड़े दर्शक नहीं हैं। हम उसी महान कथा का एक जीवित अ्थ याय हैं। ब्रह्मांड हमारी आंखों से स्वयं को देख रहा है और हमारे प्रश्नों के माध्यम से स्वयं को समझने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा है, तो अपने भीतर की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाती और तब वह ब्रह्मांड की यात्रा बन जाती है। जब आप अपने भय को समझते हैं, तब केवल एक व्यक्ति का भय नहीं समझा जाता।

आप उस मानवीय अनुभव को समझते हैं, जो असंख्य लोगों में समान रूप से मौजूद है। विज्ञान हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड को जितना हम जानते हैं, वह उससे कहीं अधिक अब भी अज्ञात है। जितनी दूर हमारी दूरबीनें पहुंचती हैं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि रहस्य अभी शेष है। यही बात भीतर की यात्रा पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह जान लेने का दावा करता है, वह शायद स्वयं को सबसे कम जानता है।

अपने भीतर उतरना किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच जाना नहीं, बल्कि सवालों के साथ जीना सीखना है।

क्या 15 साल की सत्ता भी जवाबदेही तय नहीं कर सकी?

21 जुलाई पश्चिम बंगाल की राजनीति में केवल एक तारीख नहीं है। यह एक ऐसी घटना का प्रतीक है जिसने राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई थी। उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस की सबसे आक्रामक युवा नेता थीं। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया और हर वर्ष 21 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। यही आंदोलन आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक पहचान का सबसे मजबूत आधार बना।

विपक्ष में रहते हुए ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप था कि तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने निंदार्थ प्रदर्शनकारियों पर गोलायां चलाई और दोषियों को बचाया। उन्होंने बार-बार न्यायिक जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसलिए जून 2011 में 34 वर्षों के वाम शासन का अंत हुआ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं, तो स्वाभाविक रूप से यह उन्मील जगी कि 1993 की घटना का सच सामने आएगा और दोषियों की जवाबदेही तय होगी।

इसी उद्देश्य से मई 2011 में राज्य सरकार ने ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाध्ीश न्यायमूर्ति सुशांत चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। उस समय इसे केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया।

आयोग को यह जांच करनी थी कि 21 जुलाई 1993 को वास्तव में क्या हुआ था। क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? किस स्तर पर फायरिंग का निर्णय लिया गया? क्या पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की या

आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया? क्या प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कोई ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से 13 लोगों की जान गई? इन सवालों के जवाब केवल इतिहास के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की जवाबदेही तय करने के लिए भी महत्वपूर्ण थे।

आयोग की कार्यवाही कई वर्षों तक चली। लगभग 350 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक नेता, प्रत्यक्षदर्शी, पत्रकार और मृतकों के परिजन शामिल थे। उस समय के अनेक प्रभावशाली राजनीतिक और प्रशासनिक चेहरों को आयोग के सामने उपस्थित होना पड़ा। माकपा के तत्कालीन राज्य सचिव बिमान बोस, ज्योति बसु सरकार में मंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य तथा तत्कालीन गृह सचिव मनीष गुप्ता जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने अपने बयान दर्ज कराए।

26 फरवरी 2014 को आयोग के सामने पेश हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने लगभग 50 मिनट तक अपना पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उस समय उन्हें पुलिस कार्रवाई अलग नहीं लगी थी और आज भी उनका मत नहीं बदला है। दूसरी ओर तत्कालीन गृह सचिव मनीष गुप्ता ने कहा कि वे पुलिस फायरिंग के पक्ष में नहीं थे। इन बयानों ने उस समय की निर्णय प्रक्रिया को लेकर कई नए प्रश्न खड़े किए।

आयोग ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त तुषार तालुकदार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डीसी वाजपेयी, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपरेकी जोहरी, दक्षिण डिवीजन के तत्कालीन उपायुक्त एनके सिंह तथा राइटर्स बिल्डिंग की सुरक्षा के प्रभारी संयुक्त पुलिस आयुक्त कवलजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया।

लेकिन जांच आसान नहीं

रही। तीन सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों ने आयोग के समन को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए आयोग की कार्यवाही के एक हिस्से पर रोक लगा दी। इससे जांच की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती चली गई।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुशांत चट्टोपाध्याय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणी की कि पुलिस कार्रवाई श्विना उकसावे की गई और अस्थैािनिकश्च प्रतीत होती है। उन्होंने यहां तक कहा कि यह मामला श्वलियावाला बाग हत्याकांड से भी अधिक गंभीरर दिखाई देता है। यह टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। हालांकि किसी भी न्यायिक आयोग की अंतरिम टिप्पणियां अंतिम निर्णय नहीं मानी जातीं। अंतिम निष्कर्ष उसकी पूरी रिपोर्ट में दर्ज होतें हैं।

लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। इसके बाद उन्मीद थी कि सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, उसकी सिफारिशों पर चर्चा होगी और यदि किसी अधिकाारी या राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हुई है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि आयोग ने क्या निष्कर्ष निकाले और किन सिफारिशों की अनुशंसा की। न तो विधानसभा में इस पर कोई विस्तृत चर्चा हुई और न ही कोई श्वेतपत्र जारी किया गया। परिणामस्वरूप आयोग की वर्षों की मेहनत जनता की पहुंच से बाहर रह गई।

यहीं से सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक प्रश्न शुरू होता है। यदि ममता बनर्जी विपक्ष में रहते हुए इस घटना को न्याय का सबसे बड़ा मुद्दा बनाती थीं, यदि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं जांच आयोग गठित

किया, यदि आयोग ने वर्षों तक सुनवाई कर रिपोर्ट सौंप दी, तो फिर दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

क्या आयोग ने किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं की थी? यदि की थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि नहीं की थी तो सरकार ने यह बात सार्वजनिक क्यों नहीं की? यदि कानूनी अड़चनें थीं तो जनता को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?

इन सवालों का आज तक कोई स्पष्ट सरकारी उत्तर उपलब्ध नहीं है।

यह तर्क दिया जाता है कि कई पुलिस अधिकारियों ने आयोग की कार्यवाही को अदालत में चुनौती दी थी। यह भी संभव है कि आपराधिक मुकदमे के लिए उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त न रहे हों। न्यायिक आयोग स्वयं किसी को दंडित नहीं कर सकताय वह केवल तथ्य और सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अंतिम कार्रवाई सरकार और जांच एजेंसियों को करनी होती है।

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सरकार ने कभी विस्तार से यह नहीं बताया कि आयोग की रिपोर्ट पर आगे क्या निर्णय लिया गया। यही चुप्पी विवाद और सवालों को जन्म देती है।

21 जुलाई का शहीद दिवस तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन बन गया। हर वर्ष लाखों कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचते रहे। मंच से 1993 की घटना का उल्लेख होता रहा। यह तृणमूल की राजनीतिक स्मृति और संघर्ष का प्रतीक बन गया।

लेकिन इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न भी बराबर खड़ा रहा—यदि यह घटना पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, तो न्यायिक प्रक्रिया को अंतिम मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? राजनीतिक प्रतीक के रूप में 21 जुलाई लगातार मजबूत होती गई, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया उतनी ही धुंधली होती चली गई।

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सरकार ने कभी विस्तार से यह नहीं बताया कि आयोग की रिपोर्ट पर आगे क्या निर्णय लिया गया। यही चुप्पी विवाद और सवालों को जन्म देती है।

21 जुलाई का शहीद दिवस तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन बन गया।

हर वर्ष लाखों कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचते रहे। मंच से 1993 की घटना का उल्लेख होता रहा।

यह तृणमूल की राजनीतिक स्मृति और संघर्ष का प्रतीक बन गया।

लेकिन इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न भी बराबर खड़ा रहा—यदि यह घटना पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, तो न्यायिक प्रक्रिया को अंतिम मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? राजनीतिक प्रतीक के रूप में 21 जुलाई लगातार मजबूत होती गई, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया उतनी ही धुंधली होती चली गई।

कल से दो दिन आधे शहर को नहीं मिलेगा पानी

आगरा। आज और कल जब भी पानी की आपूर्ति हो तो दो दिन की जरूरत का पानी स्टोर करके रख लें। फिर दो दिन तक आधे शहर में पानी की आपूर्ति ठप रहेगी। जीवनी मंडी वाटरवर्क्स से जुड़े रकाबगंज, बालूगंज, छीपीटोला, ताजगंज, इंद्रापुरम, हन्ना गली, विभव नगर, नौलक़्षा, सदर, बुंदू कटरा, मधु नगर, ग्वालियर रोड, डिफेंस एस्टेट, इंदगाह कॉलोनी समेत क्षेत्रों में 22 जुलाई की सुबह से 23 जुलाई की रात तक पानी नहीं आएगा। 24 जुलाई की सुबह ही जलापूर्ति शुरू हो सकेगी।

जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि ताजगंज जोन के खेराती टोला पंपिंग स्टेशन पर नमामि गंगे योजना के तहत सीवर लाइन जोड़ने का काम किया जाना है। मंगलवार को इसके लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। यहां पर पानी की पाइपलाइन को सीवर लाइन जोड़ने के लिए क्रॉस करना होगा। इस वजह से पानी की लाइन काटकर उसे सीवर लाइन के ऊपर से निकाला जाएगा। 22 और 23 जुलाई को दो दिन तक आधे शहर में पानी का संकट रह सकता है।

जलकल विभाग के अभियंता प्रेम चंद आर्य ने बताया कि इन दो दिनों में पानी की वैकल्पिक आपूर्ति के लिए टैंकर लगाए जाएंगे। लोग टैंकर से पानी प्राप्त करने के लिए जलकल विभाग के टोल फ्री नंबर 1800—2702722, कंट्रोल रूम नंबर 8192095401 तथा अगर अभियंता राजीव कुमार से 8192095734 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपनी दो दिनों की जरूरत का पानी स्टोर करके रख लेने की अपील की है।

ताड़क्वांडो में पंखुड़ी मेहरा ने जीता कांस्य, हुआ स्वागत आगरा। महाराष्ट्र के पुणे स्थित श्रीशिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 8 से 11 जुलाई तक आयोजित राष्ट्रीय ताड़क्वांडो प्रतियोगिता में पंखुड़ी मेहरा ने कांस्य पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। पदक जीतकर शहर लौटने पर दानाबाग स्थित स्वामी बाग स्कूल में साथी खिलाड़ियों ने पटका पहनाकर स्वागत किया। जिला ताड़क्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष योगेंद्र वार्पणेय ने बताया कि पंखुड़ी ने विरिष्ठ पूरसे व्यक्तिगत वर्ग के क्वार्टर फाइनल में 8.44 और सेमीफाइनल में 8.10 औसत अंक प्राप्त कर कांस्य पदक पर कब्ज़ा जमाया। संघ के उपाध्यक्ष डॉ. यूके शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, योगेंद्र वार्पणेय, संगीता शर्मा, पंकज शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अमित शर्मा, मधु शर्मा, संतोष ने बधाई दी।

सूनी पड़ी बरौली अहीर की नवीन मंडी

आगरा के बरौली अहीर की नवीन फल एवं सब्जी मंडी को संचालित कराने की मांग पर भले ही व्यापारियों का धरना सोमवार को भी जारी रहा हो लेकिन अब धरने ने नया मोड़ ले लिया है। व्यापारियों ने मंडी में मूलभूत सुविधाएं न होने से व्यापारी यहां व्यापार शुरू करने के लिए तैयार नहीं हैं। मंडी सचिव को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया। माना जा रहा कि इससे गतिरोध भी दूर होगा।

बरौली अहीर स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में व्यापारियों किसानों का धरना भले ही निरंतर जारी है लेकिन अब व्यापारियों ने मंडी समिति से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि यदि मंडी समिति सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो मंडी सुचारु रूप से संचालित होगी और गतिरोध भी समाप्त हो जाएगा। मंडी समिति ने बसई की एक अवैध सुल्लड मंडी की लगभग 150 दुकानों को नोटिस देकर बंद कराया था। इसके बाद भी कई व्यापारी मंडी के बाहर सड़क किनारे व्यापार कर रहे हैं। मंडी समिति और नगर निगम द्वारा उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है।

व्यापारियों के अनुसार नवीन मंडी में टीनशेड, बांस की टटिया, सामान रखने और फड़ लगाने जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं हैं। मंडी परिसर में 43 आवॉटेंट दुकानें हैं, जिनमें से वर्ष 2019 से केवल 5 दुकानें ही नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। अधिकांश दुकानदार बसई और सिकंदरा मंडी में व्यापार कर रहे हैं, जबकि कई ने अपनी आवॉटेंट दुकानें अब तक शुरू ही नहीं की हैं। धरने पर बैठे व्यापारियों का कहना है कि यदि सभी फूटकर विक्रेताओं का पंजीकरण कर उन्हें मंडी परिसर में नि्ध ारित स्थान उपलब्ध कराया जाए तथा टीनशेड और बांस की दुकानों जैसी सुविधाएं विकसित की जाएं, तो बसई मंडी के अधि कांश व्यापारी बरौली अहीर में व्यापार शुरू करने को तैयार हो जाएंगे। इससे मंडी का संचालन भी सुचारु रूप से शुरू हो सकेगा।

एत्मादौला स्मारक के बाहर दूटेंगे जर्जर कियोस्क

आगरा। आगरा के एत्मादौला स्मारक के सामने जर्जर कियोस्क तोड़े जाएंगे। यह फैसला पथकर सलाहकार समिति की 41वी बैठक में लिया गया है। यहां पर पर्यटकों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। अभी तक एत्मादौला आने वाले पर्यटकों के वाहन सड़क किनारे ही खड़े किए जाते हैं। इससे सड़क पर जाम लगने की समस्या बनी हुई है।

टूरिज़्म गिल्ड ऑफ आगरा के पूर्व अध्यक्ष राजीव सक्सेना ने बताया कि कई दशकों पहले कियोस्क बनाए गए थे। यह कई साल से खाली पड़े हैं और बेहद जर्जर हो चुके हैं। इन्हें तोड़कर पर्यटक वाहनों के लिए पार्किंग बनाने की मांग वह कई साल से कर रहे हैं। पथकर कमेटी में मामला उठा तो लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने इन कियोस्कों को तोड़ने पर सहमति बन गई। इसकी जगह नई पार्किंग बनाई जाएगी।

पथकर कमेटी ने इसके अलावा ताजगंज प्रोजेक्ट की टूट–फूट का काम 14 नवंबर तक पूरा करने को कहा है, वहीं शमशाबाद रोड पर इनर रिंग रोड प्लाईओवर के पास सौंदर्यीकरण का काम अगले साल 15 मई तक पूरा करना होगा। टाटा गेट से पथौली नहर तक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम इसी माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अगले साल खुलेगे आठ अंडरपासय निर्माण कार्य हुआ तेज

आगरा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने अंडरपास बनाने का कार्य तेज कर दिया है। कर्मचारी भी बढ़ा दिए हैं। अगले 10—12 महीने में ये तैयार हो जाएंगे। इनके बनने से हादसों में कमी आएगी। आसपास के लोगों को भी राहत मिलेगी।

एनएचएआई आगरा से इटावा के बीच आठ अंडर पास बना रहा है। इनका कार्य लगभग 35 फीसदी पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य को तेजी से करने के लिए कर्मचारी भी बढ़ा दिए गए हैं। अगले साल अगस्त तक यह तैयार होने के बाद लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। अभी अंडरपास नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन के लिए दिक्कत होती है। कई किमी चक्कर लगाकर दूसरी ओर जा पाते हैं। ऐसे में लंबे समय से इसकी अंडरपास बनाने की ग्रामीण मांग कर रहे थे। एनएचएआई के परियोजना निदेशक संदीप यादव ने बताया कि आठों अंडरपास बनाने का कार्य तेज कर दिया है। ये 10 से 12 महीने में शुरू हो जाएंगे।

एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि इन आठ स्थानों पर हादसे होते थे। ग्रामीण हाईवे को पार करके दूसरी ओर जाते थे, इससे हादसों की संख्या बढ़ रही थी। इस पर एनएचएआई की टीम ने सर्वे कर ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा। मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू कर दिया गया। अंडरपास बनने से हादसा में कमी आएगी लोगों की जान भी बचेगी।

ताई की मौत के बाद बनवाई थी फर्जी वसीयत, 29 साल बाद दोषी को मिली तीन साल की सजा

आगरा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट—11 आशीष कंबोज ने धोखाधड़ी से ताई की मौत के बाद जमीन की फर्जी वसीयत कराने और अन्य आरोपों के मामले में थाना सैंया क्षेत्र के गांव अयेला निवासी रामप्रकाश को दोषी पाते हुए 29 साल बाद तीन साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो गई। आरोपी भरत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

थाना खेरागढ़ में दर्ज प्राथमिकी

आगरा। दिल्ली—आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने व्यापक योजना तैयार की है। बदरपुर बॉर्डर से आगरा तक 184 किलोमीटर लंबे हाईवे की निगरानी के लिए 184 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

प्रत्येक किलोमीटर पर एक कैमरा लगाया जाएगा, जिससे हाईवे पर होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। हाईवे पर कैमरों की मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं की निगरानी की जाएगी। कैमरों की निगरानी के लिए महुअन टोल प्लाजा और कोटवन टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र बनाए

जाएंगे। यहां से हाईवे के विभिन्न हिस्सों पर लगे कैमरों की लगातार निगरानी की जाएगी। किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में संबंधित टीमों को तत्काल सूचना देकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया जा सकेगा। एनएचएआई की योजना के तहत हाईवे के प्रवेशद्वारों पर बड़ी सूचना स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। इन स्क्रीन के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात, मौसम, सड़क की स्थिति, दुर्घटना, जाम और अन्य जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे वाहन चालकों को आगे की स्थिति की जानकारी समय रहते मिल सकेगी और वे अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकेंगे।

अधिकारियों के अनुसार हाईवे पर बढ़ते यातायात और सड़क सुरक्षा की जरूरतों को देखते

दिल्ली मार्च से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन, महुअन टोल पर बढ़ाई गई सुरक्षा

आगरा। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए महुअन टोल प्लाजा पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन और टोल ऑथोरिटी ने महुअन टोल पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिये कमार कस ली है। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिये उनको समझाया जाएगा, आगे कूच ना करने के लिये निवेदन किया जायेगा।

संसद के मानसून सत्र के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों और नई दिल्ली जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के महेनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, रैलियां निकालने और प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। किसान राजधानी में आयोजित होने वाली “किसान महापंचायत” में शामिल होने जा रहे हैं। सीओ रिफाइनरी प्रवीन तिवारी ने बताया कि शासन के आदेशानुसार किसानों को समझाने के लिये महुअन टोल पर पुलिसकर्मी तैनात किए गये हैं।

फतेहपुर सीकरी के शाही तालाब में मिला युवक का शव, मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त

आगरा। आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक क्षेत्र में दीवान—ए—खास के पीछे नगीना मरिजद के समीप स्थित प्राचीन शाही तालाब में मंगलवार सुबह करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराना प्रतीत होने के कारण



क्षेत्र में तरह—तरह की चर्चाएं होती रहीं। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह ज़ुट्टी पर तैनात एसआईएस सुरक्षा कर्मियों ने तालाब में शव उतराता देखा और इसकी सूचना एएसआई के

के अनुसार, थाना सैंया के गांव अयेला निवासी गोपीचंद ने आरोप लगाया था कि उनकी ताई रामश्री निसंतान थीं। इस कारण उनकी संपत्ति के वह इकलौते वारिस हैं।

1 अगस्त, 1997 को ताई का निधन हो गया। इसके बाद ताई की जमीन से संबंधित वारिसान प्रार्थनापत्र सहायक चकबंदी अहि ाकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र के निस्तारण के दौरान गांव सरोदपुरा निवासी महावीर सिंह, भरत सिंह, विद्याराम, राजाराम और रामप्रकाश ने अज्ञात महिला को रजिस्ट्रार कार्यालय में ताई दर्शाकर जमीन की फर्जी वसीयत बनवा ली।

उनके वारिसान प्रार्थनापत्र पर आपत्ति प्रस्तुत कर खुद को जमीन का मालिक बताया। अदालत के आदेश पर 17 सितंबर, 1997 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उक्त मुकदमे में गोपीचंद के अलावा तत्कालीन ग्राम प्रधान रामा देवी, तत्कालीन उप प्रधान रामदेवी और अपिथों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गवाही दर्ज हुई। विचारण के दौरान महावीर सिंह, विद्याराम और राजाराम की मृत्यु हो गई। अदालत ने उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी।

हुए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण साबित होगी। कैमरों की निगरानी से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और दुर्घटनाओं की स्थिति में राहत कार्य भी तेजी से शुरू किया जा सकेगा। हाईवे पर आधुनिक निगरानी व्यवस्था लागू होने से दिल्ली से आगरा के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा का लाभ मिलेगा।

एसपी ट्रेफिक मथुरा राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस और एनएचएआई अधिकारियों ने साथ बैठकर हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए एनएचएआई ने एक निजी कंपनी को कैमरे लगाने का कार्य सौंप दिया है। जल्द ही कंपनी के कर्मचारी कैमरे लगाने का कार्य शुरू कर देंगे। बदरपुर बार्डर से आगरा तक

सरकारी स्कूलों का हाल - फर्स्ट एंड बॉक्स में एक्सपायर्ड देवाइयां, एक विद्यालय मिला बंद

शिक्षा अधिकारी फरह को इस मामले की विस्तृत जांच कर तीन दिन में आख्या सौंपने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालय जोधपुर में फर्स्ट—एंड बॉक्स में एक्सपायर्ड देवाइयां मिलीं और खेल सामग्री अलमारी में बंद पाई गई। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुर में परिसर में गंदगी, शौचालय का खराब रखरखाव और मध्यान्ह भोजन योजना में घोर अनियमितता देखने को मिली, जहां छात्र अलग बर्तनों का उपयोग कर रहे थे। दोनों ही स्कूलों में शिक्षक डायरी, लेसन प्लान और एकेडमिक कैलेंडर का अभाव पाया गया। बीएसए ने इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहित समस्त स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को तीन कार्य दिवस के भीतर साक्ष्यों सहित लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण न देने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बीएसए रतन कीर्ति सर्वप्रथम फरह ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय भीमनगर का निरीक्षण करने पहुंचे तो स्कूल बंद मिला। इसे देखकर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने विद्यालय के स्टाफ का वेतन और मानदेय रोकने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय जोध ापुर और उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधापुर में भी निरीक्षण के दौरान भारी कमियां और लापरवाही उजागर हुई। बीएसए ने खंड

मथुरा में लॉन्च हुआ ‘डिजिटल लेबर चौक’ ऐप, घर बैठे मिलेंगे राजमिस्त्री और मजदूर

मथुरा। मथुरा के निर्माण श्रमिकों और ठेकेदारों के लिए राहत भरी पहल करते हुए श्रम विभाग ने डिजिटल लेबर चौक एप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोजकों (ठेकेदारों) के बीच पारदर्शी एवं सरल संपर्क स्थापित करना है, जिससे रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित और सुगम हो सके।

एप के माध्यम से श्रमिक और ठेकेदार दोनों का पंजीकरण किया जाएगा। इससे नियोजकों को आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत श्रमिक आसानी से उपलब्ध होंगे, वहीं श्रमिकों को

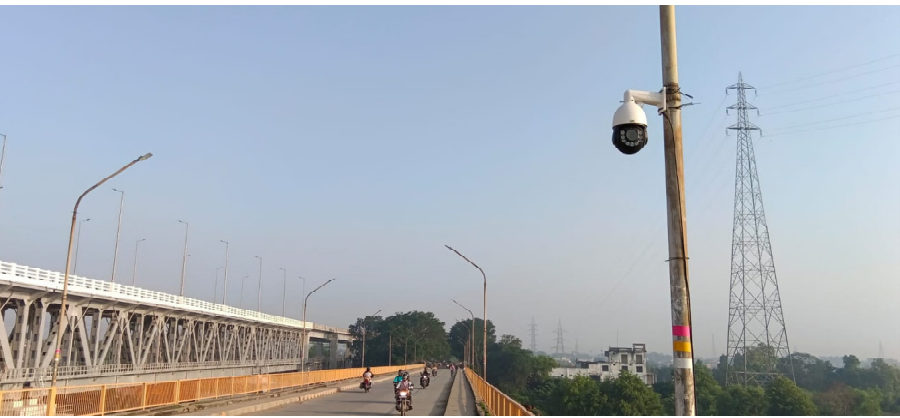
भी रोजगार के बेहतर अवसर मिलने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। श्रमिकों को एप से जोड़ने के लिए श्रम विभाग के कार्यालय में हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है, जहां पंजीकरण संबंधी हर प्रकार की सहायता उपलब्ध रहेगी।

श्रम विभाग ने जिले के सभी निर्माण श्रमिकों एवं ठेकेदारों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने की अपील की है। विभाग के अनुसार पंजीकरण के बाद श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

184 किलोमीटर तक सफर होगा ज्यादा सुरक्षित, हर किलोमीटर पर लगेगे कैमरे

184 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग में 82 किलोमीटर का हिस्सा मथुरा सीमा में आता है।

का कार्य शुरू हो जाएगा। कुछ स्थानों पर स्क्रीन लगाने का कार्य किया जा रहा है।



इसी सीमा के अंदर महुअन टोल प्लाजा है। यहां अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष बनेगा। इसके जरिए सभी कैमरों पर नजर रखी जाएगी। जल्द ही कैमरे लगाने

हाईवे पर लगने वाला एक कैमरा 500 मीटर दूरी तक सड़क पर नजर रखेगा। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक किलोमीटर पर एक कैमरा लगाया

जाएगी। इस स्क्रीन पर

वाहन चालकों को सड़क खराब होने, जाम लगने समेत

अन्य जानकारी दी जाएगी।



मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026 - श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम

आगरा। मथुरा में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। सीएमओ डॉ. राधावल्लभ ने 23 से 30 जुलाई तक गोवर्धन और आसपास के प्रमुख स्थलों पर 23 अस्थायी चिकित्सा केंद्रों पर 50 से अधिक स्वास्थ्य टीमें तैनात की हैं। ये टीमें 24 घंटे श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएंगी।

मेला व्यवस्था प्रमारी डॉ. भूदेव ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अस्थायी चिकित्सा सहायता शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों



बजे तक रहेगी।

गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के जमुनावता नहर, गोवर्धन रोडवेज बस अड्डा, दानघाटी कन्या विद्यालय, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोवर्धन रेलवे स्टेशन और राधाकुंड पुलिस चौकी सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा गोकुल, महावन और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य टीमें तैनात रहेंगी।

इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा को 4.94 लाख डॉलर चुकाने का दिया आदेश

इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स (ईएमवी) को 4.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही, राजस्थान रॉयल्स में अपनी पुरानी हिस्सेदारी को लेकर भारत में कोई भी नई कानूनी कार्रवाई करने पर स्थायी रोक लगा दी है। यह विवाद आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में

राज कुंद्रा की 11.7 फीसदी हिस्सेदारी से जुड़ा है। कुंद्रा का दावा था कि उन्हें अपनी हिस्सेदारी टीम की वास्तविक कीमत से काफी कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि, ईएमवी का कहना था कि वर्ष 2019 में हुए सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत राज कुंद्रा ने 4.94 मिलियन डॉलर लेने के बाद राजस्थान रॉयल्स के शेयरों पर अपने सभी अधिकार छोड़ दिए थे। साथ ही उन्होंने यह भी माना था कि भविष्य में इस मामले से जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई केवल इंग्लैंड

की अदालतों में होगी।

इस साल राजस्थान रॉयल्स की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी की बिक्री की प्रक्रिया शुरू होने पर राज कुंद्रा ने एनसीएलटी और बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने ईएमवी और उसके सह-संस्थापक मनोज बडाले पर धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने के आरोप भी लगाए थे। ईएमवी ने अदालत में कहा कि यह कदम 2019 के समझौते का सीधा उल्लंघन है।

राज कुंद्रा के पास ईएमवी के दावे का बचाव करने का

कोई ठोस आधार नहीं है।

2015 के शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट और 2019 के सेटलमेंट एग्रीमेंट में धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिला। दोनों समझौते राज कुंद्रा ने कानूनी सलाहकारों की मौजूदगी में अपनी इच्छा से किए थे।

कोर्ट ने पहले जारी किए गए एंटी-सूट इंजंक्शन को स्थायी कर दिया है। इसका मतलब है कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी कुकी इन्वेस्टमेंट्स अब राजस्थान रॉयल्स की इस हिस्सेदारी से जुड़े मामले में अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी लक्ष्मी मित्तल परिवार और अदार पूनावाला

नहीं कर सकते।

अदालत ने राज कुंद्रा और कुकी इन्वेस्टमेंट्स को संयुक्त रूप से 4.94 मिलियन डॉलर की सेटलमेंट राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि समझौते का बार-बार उल्लंघन होने के कारण ईएमवी ने उसे समाप्त करने का फैसला सही तरीके से लिया था।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब ईएमवी और उसके शेयरधारकों ने राजस्थान रॉयल्स में अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी लक्ष्मी मित्तल परिवार और अदार पूनावाला

के नेतृत्व वाले समूह को बेच दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1.65 बिलियन डॉलर की यह डील आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील में से एक मानी जा रही है। साल 2015 में आईपीएल में सट्टेबाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद राज कुंद्रा राजस्थान रॉयल्स से अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी हिस्सेदारी भी ट्रांसफर कर दी थी, जिसे लेकर बाद में यह कानूनी विवाद शुरू हुआ।



डीएसपी मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना डीजीपी से की मुलाकात

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और तेलंगाना पुलिस में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) मोहम्मद सिराज ने सोमवार को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी.वी. आनंद से शिफ्टाचार मुलाकात की। डीजीपी कार्यालय में हुई इस बैठक के दौरान आईजी (पी एंड आई) गजाराव भूपाल और डीएसपी (स्पोर्ट्स) रामाराव भी मौजूद रहे।

भारत की टी-20 विश्व कप 2024 जीत के बाद मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी और आवासीय भूखंड देने की घोषणा की थी। इसके बाद अगस्त 2024 में राज्य मंत्रिमंडल ने मोहम्मद सिराज और विश्व चौंपियन मुक़ेबाज निखत जरीन को ग्रुप-1 श्रेणी के डीएसपी पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

इसके लिए राज्य सरकार ने तेलंगाना (सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ संरचना और वेतन व्यवस्था का युक्तिकरण) अधिनियम, 1994 में संशोधन भी किया। अक्टूबर 2024 में सिराज ने आधिकारिक रूप से डीएसपी का पदभार ग्रहण किया। राज्य सरकार ने उन्हें हैदराबाद के जुबली हिल्स, रोड नंबर-78 पर 600 वर्ग गज का आवासीय भूखंड भी आवंटित किया है।

इस बीच डीजीपी सी.वी. आनंद ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस वेलफेयर सोसायटी और आरोग्य भद्रता (हेल्थ प्रोटेक्शन) योजना की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण तेलंगाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि विभाग पुलिसकर्मियों के बच्चों को मेरिट स्कॉलरशिप और मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। साथ ही जेईई, नीट और अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

डीजीपी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए विवाह ऋण, चिकित्सा ऋण, शिक्षा ऋण, मेरिट छात्रवृत्ति, अतिरिक्त कॉर्पस बीमा तथा विभिन्न अनुदान आधारित सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

बैठक में हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की भी समीक्षा की गई। इसके तहत वर्ष 2025 में 33,126 पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने उपचार का लाभ उठाया, जबकि जून 2026 तक 12,392 लाभार्थियों का इलाज किया गया। इस योजना पर वर्ष 2025 में 181.74 करोड़ रुपये और जून 2026 तक 73.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए। डीजीपी ने कहा कि यह पुलिस विभाग की कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



बने रहे।

बता दें कि एम्बाप्पे ने तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ दो गोल किए। हालांकि फ्रांस को 6-4 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन दो गोलों की बदौलत उनका कुल गोलों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने लगातार दूसरी बार विश्व कप का गोल्डन बूट अपने नाम किया। इससे पहले भी उन्होंने वर्ष 2022 के विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया था। गौरतलब है कि लगातार दो विश्व कप में यह उपलब्धि हासिल

अर्जुन एरिगैसी ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को दी मात

भारत के ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 के पांचवें दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को काले मोहरों से हराकर अंक तालिका में संयुक्त बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के साथ एरिगैसी के 3.5 अंक हो गए हैं और वह फ्रांस के ग्रैंडमास्टर अलीरेजा फिरोजा के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं।

टूर्नामेंट में अब केवल दो दौर शेष हैं, ऐसे में खिताबी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। उजबेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने भी काले मोहरों से जीत दर्ज कर खिताब की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। उनके तीन अंक हैं और वह शीर्ष खिलाड़ियों से केवल आधा अंक पीछे हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के चौथे संस्करण में आठ ग्रैंडमास्टर्स राउंड-रॉबिन प्रारूप में मुकाबला कर रहे हैं। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 75 लाख रुपये है और इसमें खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण फिडे सर्किट अंक भी मिल रहे हैं।

अर्जुन एरिगैसी और डी. गुकेश के बीच हुए मुकाबले की शुरुआत तमिलनाडु के युवा शतरंज खिलाड़ी जेशुआ जे. के औपचारिक उद्घाटन चाल से हुई। जेशुआ सबसे कम उम्र में एरीना फिडे मास्टर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। मुकाबले में एरिगैसी ने काले मोहरों से बेहद संयमित खेल दिखाया। मध्य खेल (मिडिल गेम) में गुकेश की कुछ गलत चालों का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और धीरे-धीरे मैच पर नियंत्रण बना लिया। जब यह साफ हो गया कि एरिगैसी का इंडीश फाइनल का प्यादा खीन बनने जा रहा है, तब विश्व चैंपियन गुकेश ने 63वीं चाल पर हार स्वीकार कर ली।

एक अन्य मुकाबले में नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन के खिलाफ काले मोहरों से आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा और अंततः 38 चालों के बाद निहाल को हार माननी पड़ी।

फ्रांस के ग्रैंडमास्टर अलीरेजा फिरोजा और रूस के विभिन्नी आंद्रेइकिन के बीच मुकाबला 41 चालों के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस परिणाम के बावजूद फिरोजा 3.5 अंकों के साथ संयुक्त बढ़त बनाए हुए हैं।

आईएसएसएफ विश्व कप के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम का एलान

नई दिल्ली। भारत ने आईएसएसएफ विश्व कप (राफ़लधर्पिस्टलवर्ल्डगन) के लिए 36 सदस्यीय टीम चुनी है। चीन के हांगझोऊ में 20 से 29 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वर्णिल कुसाले भारतीय टीम की अगुआई करेंगे। आईएसएसएफ विश्व कप प्रतियोगिता 22 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में मेडल का फैसला होगा। टूर्नामेंट का समापन 28 जुलाई को 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम और ट्रैप मिक्स टीम इवेंट्स के फाइनल के साथ होगा। भारतीय दल में राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट्स

के लिए अनुभवी ओलंपियन और उभरते हुए खिलाड़ियों का मिश्रण है। खिलाड़ी व्यक्तिगत और मिक्स टीम इवेंट्स, दोनों में हिस्सा लेंगे। मनु और स्वर्णिल के साथ ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह, सुरुचि, इलावेनिल वलारिवन, सिफ्ट कौर सामरा, सोनम उत्तम मस्कर, अनीशा भनवाला, राजा डिल्लों, गनेमत सेखों और ओलंपियन अनंत जीत सिंह नरुका जैसे जाने-माने शूटर भी शामिल हैं।

पुरुषों की 50 मीटर राइफल थी ग्रीजेशन टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल शामिल हैं, जबकि महिलाओं के इवेंट में आशी चौकसे, विदर्शा के. विनोद और सिफ्त कौर सामरा हिस्सा लेंगी। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि, संयम और ईशा सिंह भारत की चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के इवेंट में के दारलिंग ग. बी. उचागनवे,

कमलजीत और आकाश भारद्वाज शामिल होंगे। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत की मौजूदगी होगी। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम में अनीशा भनवाला, ओंकार सिंह और भावेश शेखावत को चुना गया है।

शॉटगन इवेंट्स में, उदावीर सिंह जाजी, भवनीश मेंदीरता और विगान कपूर पुरुषों के ट्रैप इवेंट में हिस्सा लेंगे। महिलाओं की ट्रैप टीम में प्रगति दुबे, कीर्ति गुप्ता और राजेश्वरी कुमारी हिस्सा होंगी। पुरुषों की स्कीट टीम में गुरजोत सिंह खंगुरा, परमपाल सिंह गुरोन और अभय सिंह सेखों शामिल हैं, जबकि गनेमत सेखों, दर्शना राठौर और यशवीरा राठौर महिलाओं की स्कीट प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

राइफल इवेंट्स में, पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु डिल्लों, शाहू

तुषार माने और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं, महिलाओं की प्रतियोगिता में इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और साक्षी सुनील पडेकर को चुना गया है। इसके अलावा, भारत 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम और ट्रैप मिक्स टीम इवेंट्स में भी टीमें उतारेगा।



ओपन का खिताब जीतकर शानदार लय में लौटी भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधू मंगलवार



से शुरू हो रहे चीन ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगी लेकिन पुरुष युगल की शीर्ष जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कंधे की चोट से उबर

रहे सार्विक के कारण इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी। भारतीय टीम बीडब्ल्यूएफ विश्व

ओलंपिक पदक विजेता सिंधू ने जापान ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में तीन बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को हराया।

उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपने सभी मुकाबले सीधे गेमों में जीतकर खिताब अपने नाम किया। सिंधू अपने अभियान की शुरुआत हमवतन उन्नति हुड्डा के खिलाफ करेंगी। दूसरे दौर में उनका सामना चीन की चौथी

दूर पर पिछले सप्ताह के शानदार प्रदर्शन की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। सिंधू लगभग दो वर्ष बाद जापान ओपन का खिताब जीतकर बेहतरीन लय में चीन पहुंची हैं। दो बार की

वरीयता प्राप्त चैन यू फेई से हो सकता है। महिला एकल में भारत की अन्य खिलाड़ी देविका सिहाग अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान के खिलाफ

करेंगी।

पिछले महीने सिंगापुर ओपन सुपर 750 का खिताब जीतने वाले सात्विक और चिराग ने जापान ओपन से भी सात्विक की बार-बार उभर रही कंधे की चोट के कारण नाम वापस ले लिया था। अब दोनों ने विश्व चैंपियनशिप से पहले पूरी तरह फिट होने के उद्देश्य से चीन ओपन नहीं खेलने का फैसला किया है। विश्व चैंपियनशिप 17 वर्ष बाद भारत में आयोजित होने जा रही है। पुरुष एकल में भारत की चुनौती का जिम्मा पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन, विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर काबिज आयुष शेट्टी और अनुभवी एचएस प्रणय संभालेंगे। लक्ष्य सेन शुरुआती दौर में जापान के युशी तनाका से भिड़ेंगे।

आयुष शेट्टी का सामना इंडोनेशिया के अली फरहान से होगा, जबकि 2023 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता प्रणय पहले दौर में मलेशिया के लीआंग जुन हाओ से खेलेंगे। मिश्रित युगल में भारत की उम्मीदें तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी पर टिकी होंगी, जिनका पहले दौर में चीन की पांचवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी गुओ शिन वा और चैन फांग हुई से मुकाबला होगा। रोहन कपूर और रुचिका शिवानी गड्डे की जोड़ी का सामना पहले दौर में शीर्ष वरीय चीन के फेंग यान झे और हुआंग डोंग पिंग से होगा। पुरुष युगल में हरिहरन अम्साकरुण और एम.आर. अर्जुन की जोड़ी अपने पहले मुकाबले में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से भिड़ेंगी।

पैरा स्पोर्ट्स में भारत को 5-6 पदकों की उम्मीद

नई दिल्ली। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए रवाना हो रहे भारतीय पैरा खिलाड़ियों से देश को रिकॉर्ड प्रदर्शन की उम्मीद है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने सोमवार को कहा कि भारतीय पैरा दल इस बार पांच से छह पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है।

भारतीय पैरा टीम के विदाई समारोह के दौरान झाझरिया ने कहा कि भले ही इस बार खेलों का दायरा सीमित किया गया है और पैरा टेबल टेनिस जैसे कुछ इवेंट्स को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा, इश्मारे पैरा खिलाड़ी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रिकॉर्ड प्रदर्शन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत कम से कम 5-6 पदक जीत सकता है। भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल सोमवार रात स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो के लिए रवाना हो गया। भारतीय खिलाड़ी पांच अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे।

राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत 2002 मैनचेस्टर संस्करण से हुई थी। तब से अब तक भारत ने कुल आठ पदक जीते हैं। इनमें दो स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं।

पिछले दो दशकों में भारत का पैरा स्पोर्ट्स लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने पैरालंपिक, एशियाई पैरा खेल, विश्व चैंपियनशिप समेत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है।

